ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-1* February- 2021
Innovation The Research Concept

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के वित्तीय विवरणों का आधुनिक विश्लेषण, विशेष संदर्भ आगरा जोन

Modern Analysis of Financial Statement of Uttar Pradesh Power Corporation Limited Dakshinanchal Vidhut Vitran Nigam Limited (DVVNL) Special Reference Agra Zone (Period 01-04-2018 to 31-03-2019)

Paper Submission: 02/02/2021, Date of Acceptance: 23/02/2021, Date of Publication: 24/02/2021

विमल कुमार
शोधछात्र,
वाणिज्य विभाग,
ए0के0पी0जी.कॉलेज,
बी0आर0अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा,
शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश,
भारत

गिरिराज कुमार गुप्ता
रिटायर्ड प्रिन्सिपल
वाणिज्य विभाग,
ए0के0पी0जी.कॉलेज,
बी0आर0अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा,
शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद की खराब वित्तीय स्थिति और बढती विद्युत (बिजली की कमी) ने राज्य के बिजली उद्योग के कट्टरपंथी सुधारों का आहवान किया। हालांकि हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि कार्यान्वित किया जा रहा सुधार मॉडल विद्युत परिषद की पिछली समस्याओं के पूर्ण निदान पर आधारित है। बिजली खरीद की उच्च लागत, मनमाने मूल्य हास, मानदण्ड। कृषि खपत का गलत विवरण और सब्सिडी आदि की प्रमुख की अधिक रिर्पोटिंग। परिषद के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित करने में खराब रखरखाव, खराब उत्पादकता, उच्च टी एण्ड डी नुकसान, खराब बिलिंग, दक्षता और कृषि के लिए उच्च सब्सिडी के रूप में महत्व पूर्ण कारण थे। कारणों के पूर्व सेट की कमी के अलावा सुधार प्रक्रिया, प्रस्तावित मॉडल में तोड़फोड़, प्रवण अन्तराल और इसके कार्यान्वयन की तर्थत हैण्डलिंग जैसे अन्य नुकसान से ग्रस्त हैं। ये नुकसान समता मूलक बिजली वितरण के सामाजिक उद्देश्य के पुर्नगठन में परिलक्षित होते हैं। ''राष्ट्रहित में बिजली बचायें'' इन नुकसानों को प्रतिविम्बित किया गया है। न्यायसंगत बिजली वितरण के सामाजिक उद्देश्य की मरम्मत भारी प्राधिकरण दायित्व लेकिन विद्युत नियामक आयोग पर थोड़ी जबावदेही आयोग के सदस्यों के रूप में चयन के लिए पात्र व्यक्तियों की प्रोफाइल और नौकरी की जटिल तकनीकी आर्थिक ज्ञान आवश्यकताओं और गैर सहभागिता दृष्टि के बीच अन्तर। कार्यान्वयन प्रक्रिया और परिषद के कर्मचारियों की सेवाओं की चिन्ताओं और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की मान्यता का अभाव। ऐसा लगता है कि प्रस्तावित सुधार मॉडल को अतीत की गलतियों के कारण वित्तीय बोझ से बचने के लिए हतासा से बाहर निकलने की कल्पना की गयी थी, न कि तकनीकी ओर प्रतिस्पर्धी माहौल में अर्न्तराष्ट्रीय बदलाव को ध्यान में रखते हुए अतीत की नीतियों, संरचनाओं और प्रणालियों के पुनः उन्मुखीकरण के रूप में है।

The poor financial condition of Uttar Pradesh State Electricity Council and rising power (shortage of power) called for radical reforms of the state's power industry. However, our analysis shows that the improvement model being implemented is based on a complete diagnosis of the previous problems of the Electricity Council. High cost of power purchase, arbitrary price loss, norms. Misrepresentation of agricultural consumption and major reporting of subsidies etc. Significant factors in influencing the council's financial performance were poor maintenance, poor productivity, high T&D losses, poor billing, efficiency and high subsidies for agriculture. In addition to the lack of a prior set of reasons, the reform process suffers from other disadvantages, such as sabotage in the proposed model, prone intervals, and handheld handling of its implementation. These losses are reflected in the reorganization of the social purpose of equity-oriented power distribution. The repair of the social purpose of equitable power distribution Heavy Authority Liability but little accountability on the Electricity Regulatory Commission The difference between the profile of persons eligible for selection as members of the Commission and the complex technical economic knowledge requirements and non-participatory vision of the job. Lack of recognition of concerns and training requirements of the implementation process and services of council staff. It is likely that the proposed reform model was conceived out of desperation to avoid the financial burden due to mistakes of the past, rather than taking into account the international shift in technological and competitive environment, policies, structures and systems of the past.

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-1* February- 2021
Innovation The Research Concept

मुख्य शब्द : दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि0, तरलता अनुपात, चालू अनुपात, स्कन्ध अनुपात, स्वामित्व अनुपात आदि।

Dakshinchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Liquidity Ratio, Current Ratio, Wing Ratio, Ownership Ratio etc.

प्रस्तावना

DVVNL Map

Dvvnl History

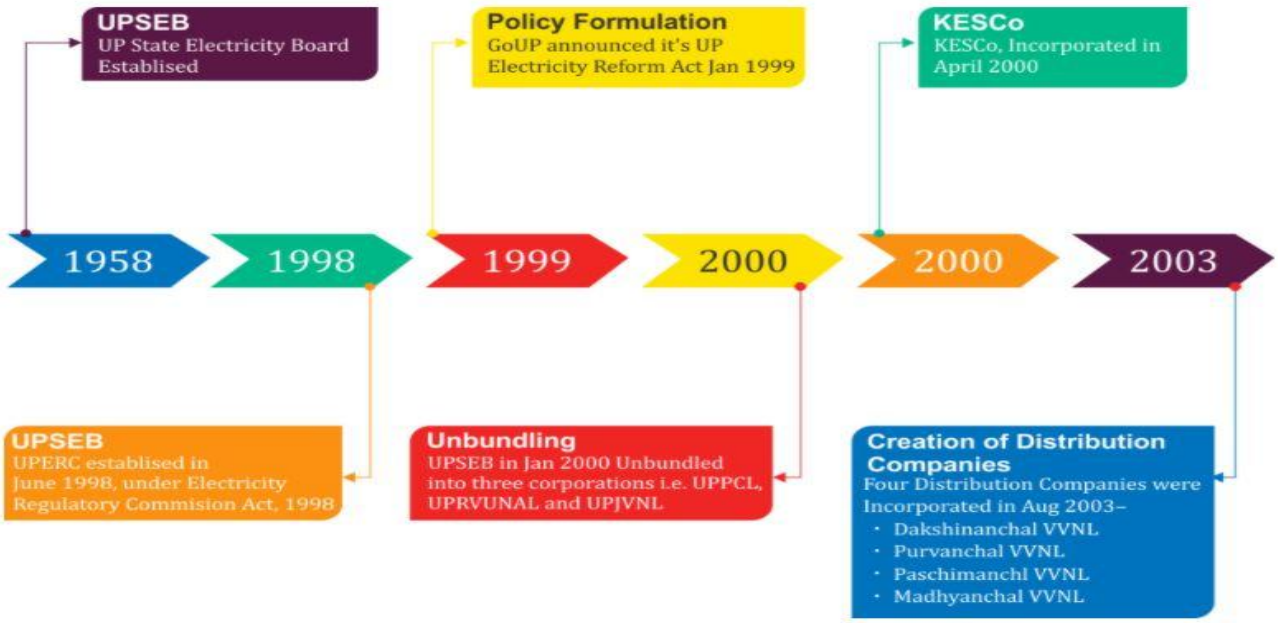

1. Functioning started in June, 2003
2. Consists of 21 Districts divided into 5 Zones- Agra, Aligarh, Jhansi, Kanpur, Banda for better management.
3. Total system capacity was 2369 MVA in 2003-04 which is increased to 6689 MVA in 2012-13.
4. In 2003-04 Input Energy was 8447 MUs which increased to 17571 MUs by 2012-13, thereby increase of 108%.
5. Revenue realized in 2003-04 was Rs.1040 Crores which has gone up to Rs. 3399 Crores in 2012-13, substantial increase of 227%.

Dvvnl Zone Distribution

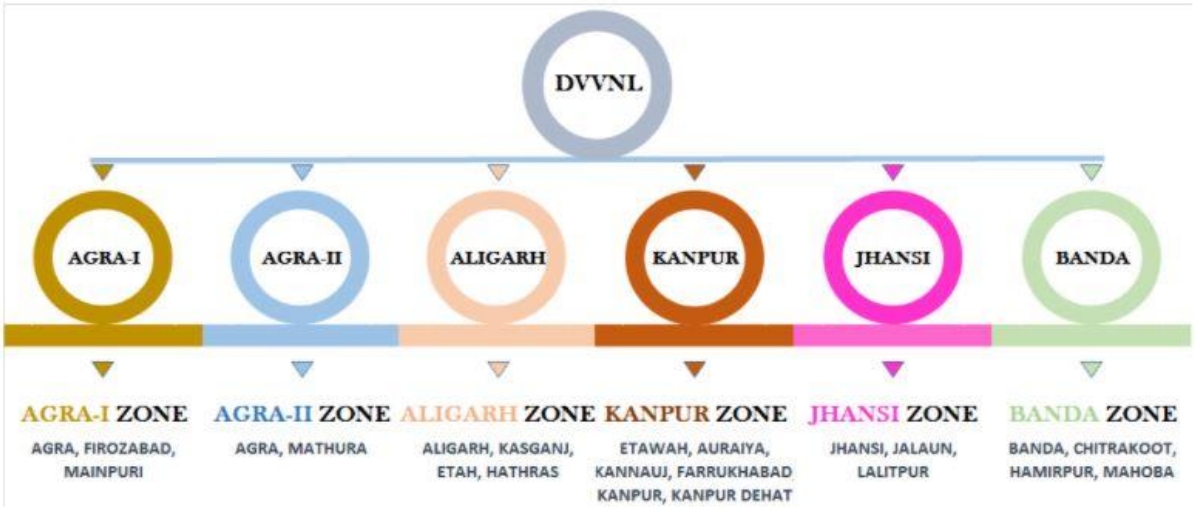

Organizational Structure

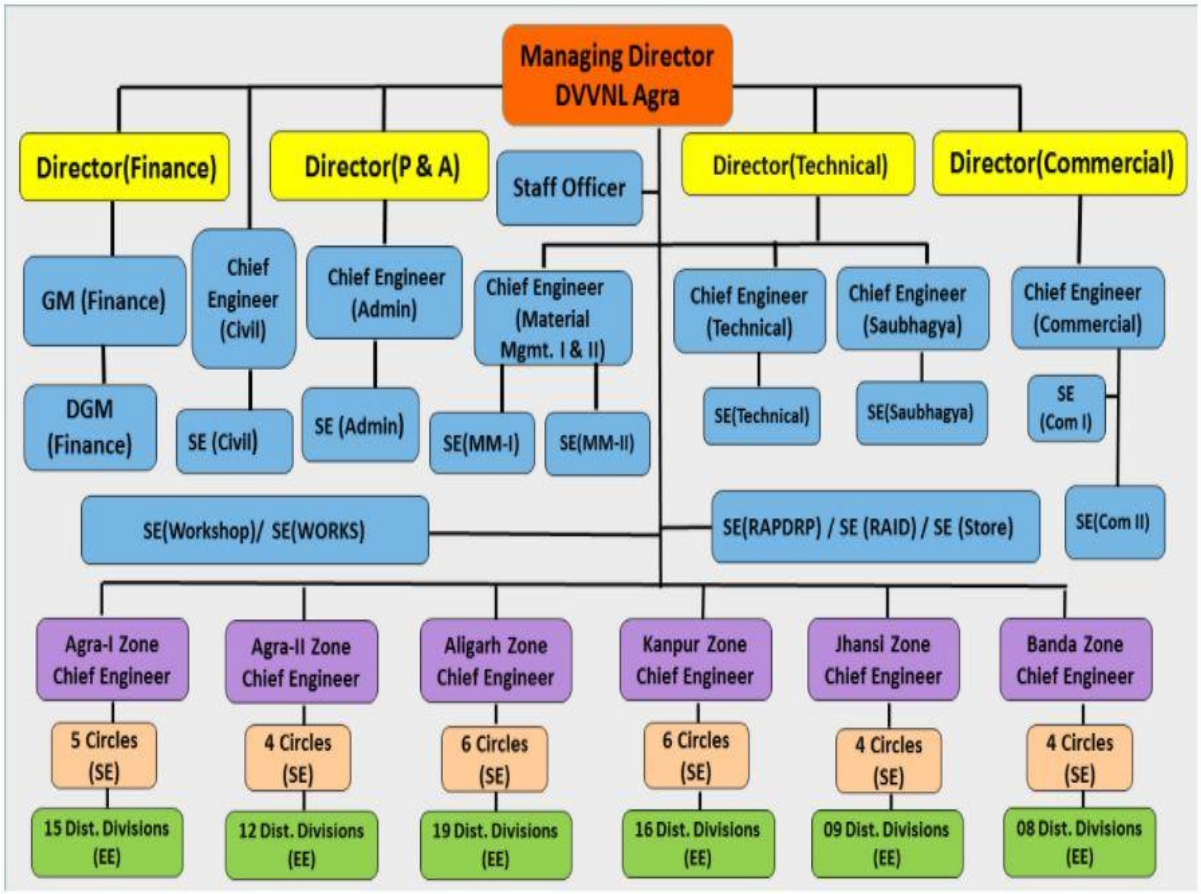

Statistical Detail of Dvvnl

Agra

Population	Detail
Rural	89669
Urban	344228
Total	433897

Transformer in Transmission

	District	Name of Sub Station	Voltage Ratio	Capacity
Load 400 KVA	Agra	400 KV S/S Agra	400/220/33	2x315
			220/132	2x160
Load 220KV	Agra	220 KV S/S Agra	220/132	3x100
			132/33	1x63
			132/33	1x40
Load 132KV	Agra	132KV S/S Agra (Cantt)	132/33	2X40
Load 132KV	Agra	132KV S/S Agra (Foundari-Nagar)	132/33	1X63
			132/33	1X40
	Agra	132KV S/S Agra (Taj)	132/33	3X40
	Agra	132KV S/S Shamshabad	132/33	2X40
	Agra	132KV S/S Bodla	132/33	2X40

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के अध्ययन के उद्देश्य

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अध्ययन करने का उद्देश्य यह है कि विगत 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक के आर्थिक वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए विगत पांच वर्षों में सम्पत्ति में कमी आना तथा आर्थिक दायित्वों में वृद्धि लगातार बढ रही है। यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि क्या कारण रहे हैं, जिनके द्वारा पॉवर कॉर्पोरेशन के वित्तीय स्थिति या हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। विगत पांच वर्षों के वित्तीय विवरणों के अध्ययन में यह जानने की कोशिश की गयी है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में लाइनहानि अधिक बढ़ी है और पॉवर कॉर्पोरेशन के वित्तीय व्यवस्था में अधिक गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जिसमें 90,000/–रूपये का तार चोरी कर बेचा जाना एवं निगम के नैतिक लिपिकों द्वारा राजस्व को कम दिखाकर विभाग में जमा किया है और वसूली के अर्न्तगत जमा राजस्व की रसीदों का फर्जी तथा डुप्लीकेट प्रति छपवाकर नकली रसीदों का दिया जाना तथा आर्थिक गबन, धोखाधड़ी की शिकायतों का मिलना बड़ी दुखद घटना है। पॉवर कॉर्पोरेशन में लाइन हानियों को रोकने के लिए चैकिंग अभियान तथा पारदर्शी व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय विवरणों का परीक्षण एवं अध्ययन कर आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उपायों पर विचार प्रस्तुत करना है। वित्तीय विवरणों के दायित्वों को कम करने के लिए विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार करना तथा बेहतर सेवा देकर राजस्व में प्रगति करने के अवसरों की तलाश निरंतर जारी रहनी चाहिए। साथ ही आर्थिक वित्तीय विवरणों में सम्पत्ति में वृद्धि अवश्य करने के अवसरों की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है।

शोध/अनुसंधान की प्रविधियाँ/उपकरण

अनुसंधान कार्य में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए हम अनुसंधान करने के जिन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है वे निम्नलिखित हैं :–

अनुपात विश्लेषण

जिसके अर्न्तगत हम वित्तीय विवरणों में प्रत्येक मद का विश्लेषण अनुपात विश्लेषण के अर्न्तगत किया जायेगा, जो निम्न प्रकार है :–

अनुपात विश्लेषण का अर्थ

वित्तीय विवरणों में प्रदत्त व्यवसायिक तथ्यों का व्यक्तिगत रूप में कोई महत्व नहीं होता है। अतः उनके आधार पर कोई भी उचित निष्कर्ष उस समय तक नही निकाला जा सकता है, जबकि विभिन्न मदों के बीच कोई सम्बन्ध स्थापित नही किया जाता है।

अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य

अनुपात विश्लेषण से विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, प्रमुख रूप से सम्बन्ध प्रबन्ध के आधारभूत कार्य योजना से हैं। योजना, समन्वय, नियंत्रण एवं पूर्वानुमान के कार्य में सहायता पंहुचाना ही अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य होता है।

अनुपात का महत्व/सीमांए

वित्तीय विवरणों का निर्वाचन में अनुपात विश्लेषण का महत्व ही अधिक होता है। अनुपातों के

आधार पर विश्लेषण अंकों सतह तक पंहुच सकता है। जिस रूप में संख्यांए वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गयी होती हैं।

अनुपात विश्लेषण का वर्गीकरण

वित्तीय विवरण के आधार पर वर्गीकरण

यह कि वर्गीकरण उन विवरणों के ऊपर आधारित है, जिनमें प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर अनुपात निकाले जाते हैं, क्योंकि लेखा सम्बन्धी सूचनांए दो विवरणों 1. आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) 2. लाभ–हानि खाता (Profit & Loss A/c) से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वर्गीकरण के अर्न्तगत निम्न को शामिल कर सकते हैं।

आर्थिक चिट्ठा का अनुपात

इसके अर्न्तगत निम्न अनुपातों को शामिल किया जाता है :–

1. तरलता का अनुपात Liquidity Ratio
2. चालू अनुपात Current Ratio
3. स्कन्ध अनुपात Stock Ratio
4. स्वामित्व अनुपात Propritory Ratio

लाभ–हानि अनुपात

1. आर्वत बिक्री अनुपात Turnover Sales Ratio
2. खर्चा अनुपात Expenses Ratio
3. आय अनुपात Income Ratio

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-1* February- 2021
Innovation The Research Concept

FY 2019-20								
Generating Stations	Units (MU)	Fixed Charges (Rs. Crore)	Per Unit Fixed (Rs. kWh)	Energy/ Variable Charges (Rs. Crore)	Per Unit EC/VC (Rs. kWh)	Other Cost (Rs. Crore)	Total Cost (Rs. Crore)	Per Unit Total Cost (Rs. /kWh)
Meja Thermal Power Plant	760.39	247.02	3.25	248.41	3.27	5.33	500.77	6.59
LANCO	6,725.85	637.11	0.95	1,356.15	2.02	291.30	2,284.56	3.40
BEPL BARKHERA	82.96	92.42	11.14	30.70	3.70	98.28	221.41	26.69
BEPL KHAMBHAKHERA	73.16	89.64	12.25	26.96	3.69	1.30	117.91	16.12
BEPL KUNDRAKHI	116.26	89.36	7.69	37.89	3.26	-0.77	126.48	10.88
BEPL MAQSOODAPUR	93.89	85.71	9.13	35.04	3.73	1.78	122.53	13.05
BEPL UTRAULA	109.71	89.94	8.20	37.54	3.42	-2.11	125.37	11.43
KSK MAHANADI	4,772.38	1,219.31	2.55	1,331.69	2.79	-50.39	2,500.61	5.24
LALITPUR	6,916.85	2,858.00	4.13	1,990.37	2.88	629.72	5,478.09	7.92
M.B. POWER	2,273.46	669.32	2.94	435.51	1.92	904.11	2,008.94	8.84
PRAYAGRAJ POWER	8,472.86	1,247.83	1.47	2,068.15	2.44	-79.01	3,236.98	3.82
R.K.M. POWER	2,074.84	547.47	2.64	389.43	1.88	13.82	950.72	4.58
ROSA-1&2	5,637.22	1,269.43	2.25	1,729.06	3.07	21.31	3,019.80	5.36
SASAN	3,778.25	55.68	0.15	434.43	1.15	90.04	580.15	1.54
TRN ENERGY	1,602.07	292.24	1.82	264.81	1.65	434.28	991.34	6.19
NABINAGAR POWER PROJECT	271.16	85.73	3.16	57.54	2.12	-1.34	141.94	5.23
Ghatampur								
Sub-Total	**48,670.85**	**10,380.34**		**11,387.71**		**2,481.15**	**24,249.20**	**4.98**
Total	**108,242.21**	**17,935.51**		**24,260.69**		**3,402.91**	**45,599.11**	**4.21**
Other Sources Sub-total	1,646.92	-	-	1,483.05	9.01	0.04	1,483.09	9.01
Cogen/ Captive	3,228.14	-	-	1,237.49	3.83	-162.12	1,075.37	3.33
Solar	**2,100.25**	**-**	**-**	**937.62**	**4.46**	**-0.15**	**937.46**	**4.46**
Non-Solar (Renewable)								
WIND	950.88	-	-	326.21	3.43	-	326.21	3.43
Sub-Total	**950.88**	**-**		**326.21**			**326.21**	
NVVN Thermal	814.30	-	-	246.35	3.03	11.45	257.81	3.17
NVVN Solar	298.34	-	-	215.85	7.24	4.02	219.88	7.37
Transmission Charges	-	-	-	-	-	5,008.90	5,008.90	-
Grand Total	**117,281.03**	**17,935.51**	**1.53**	**28,707.27**	**2.45**	**8,265.05**	**54,907.83**	**4.68**

Bulk Supply Tariff (BST)

3.3.3. For the purpose of allocating the power purchase cost to the Discoms for FY 2019-20 as per

Differential Bulk Supply Tariff (DBST) approach, the first shall be to determine the Bulk Supply Tariff (BST) based on the consolidated projected power purchase cost for FY 2020-21. Accordingly, the BST for FY 2020-21 on consolidated basis is shown in the table below:

Table 3-5: Bulk Supply Tariff for FY2019-20

Particulars	Approved	Provisional
Power Purchase cost (Rs Crore)	51438.30	54,907.83
Power Input (MU)	113,747.99	117,281.03
Inter-State Trans Losses (%)(% Computed on Total Input Energy)	2.13%	1.55%
Inter-State Loss (MU)	2,428.31	1,821.15
Input at Transco End (MU)	111,319.68	115,459.88
Intra-State Trans Losses (%)	3.56%	3.53%
Input as Discom End (MU)	107,356.70	111,384.15
BST at Discom Periphery (Rs/Kwh)	**4.79**	**4.93**

Differential Bulk Supply Tariff (DBST)

3.3.4. In Suo Moto Order dated September 25, 2018 the Commission had given the following directions:

"

1. *A model on "Allocation of Power Purchase Agreement (PPA's) among Discoms with in the State of Uttar Pradesh (UP)" for FY 2018-19, wherein, DBST for various Discoms is based on the consumer mix and through rate.*

2. *A model on "Allocation of Power Purchase Agreement (PPA's) among Discoms with in the State of Uttar Pradesh (UP)" for FY 2018-19, wherein, the existing PPA's, which already have a provision for allocation of power among the State Discomsmaybe considered, as per the allocation to the respective Discoms, while for the rest of the power purchase agreements, the allocation may be done, in such a manner that, overall DBST concept is achieved, thereby creating a hybrid model."*

3.3.5. In Suo Moto Order dated December 13, 2018 the Commission had given the following directions:

"

...However, consideration should also be given to the demography of the State given its size in terms of area and population as a result of which the consumer mix of every Discom is in huge contrast to each other. In view of this, linking the same with through rate of each Discom ensures that Discoms with a non-favourable consumer mix, which is uncontrollable factor, will have a level playing field."

3.3.6. The Director (Tariff), UPERC provided step by step methodology on 16.05.2019. Following the instructions, Distribution licensees submitted their DBST computation accordingly alongwith ARR submission for FY 2019-20 to Hon'ble Commission.

सम्बन्धित शोध–साहित्य

ऐ.वी. जॉर्ज 2000

ऐ.बी. जॉर्ज ने 2004 में अपने विचारों को प्रकट किया है कि उच्च स्तर पर विद्युत वितरण की कई एक कारक जिसमें घरेलू खपत में वृद्धि और करों में छूट विद्युत प्रदान करनी चाहिये। घटती हुई विद्युत दरों को लागू करना चाहिए। विद्युत उत्पादन प्रणाली के क्षेत्र में केरला राज्य का योगदान सराहनीय रहा है। केरला राज्य विद्युत परिषद इस जटिल समस्या का उत्तर देता है और इसको सरल भी बनाता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में विद्युत उत्पादन प्रणाली निर्भर करती है। निजी अधीनस्थ सार्वजनिक इकाईयों में 3 अभियान पहले से ही संचालित हैं और इनके साथ ही पांच पाइपलाइन प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में लागू किया गया है।

के.पी. कन्नन एन बीथा मोहन पिल्लई 2001

ने भारत में विद्युत परिक्षेत्र की दशा में यह लिखा है। उन्होंने महत्वपूर्ण पहलुओं की अकुराल दरों को राज्य विद्युत प्रत्यावेदन को कार्यप्रणाली पर उन्होंने अपना ब्यान परिभाषित किया है। उन्होंने भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन पर अपना ब्यान दिया है। उन्होंने भौतिक प्रदर्शन

पर ऐसे पहलुओं का तकनीकी कुशलता पर ध्यान आकर्षित किया है। संग्रहण एवं विभाजन दोनों में कटौती हुई है। संस्थागत एवं संगठनात्मक अकुशलताओं के सम्बन्ध में संभव आंकलन करने पर वित्तीय प्रदर्शन पर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य विद्युत परिषदों ने इनका निरीक्षण किया।

माधव गोड़वोले 2002

माधव गोड़वोले ने महसूस किया है कि तार्किता करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उन्होंने कहा है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए और विधायका के द्वारा विद्युत परिनियमावली आयोग का गठन केन्द्र स्तर पर होना चाहिए। लेकिन विद्युत परिनियमावली आयोग का कार्य अब तक संतोषजनक रहा है। उन्होंने संकेत किया कि नियामक एक समय था कि विद्युत नियामक आयोग ने अपनी उपलब्ध शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग किया था और भविष्य में विद्युत क्षेत्र के सम्बन्ध में उप नियमों पर निर्भर करेगा।

या सुसी सुजुकी 2002

या सुसी सुजुकी ने विद्युत ढांचे और विदेशी सहायता नीतियों की ओर भारत की विद्युत क्षमता इकाईयों पर प्रकाश डाला या सुसी सुजुकी ने निष्कर्ष निकाला कि जापान के कार्यालयी विकास सहायक इकाईयों को सावधानीपूर्वक इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। कार्य आदेश के परिपेक्ष्य में अमग निर्णय सह सम्बन्ध की अनोखी किराया मांग प्रकिया जो भारत में विशेष रूप से राजनैतिक रूप से विद्युत विभाग के करों को अदा करने में एक कमजोरी है। जिनकी आलोचना की जानी चाहिए और विद्युत विभाग के अपर्याप्त सुविधाओं का विरोध होना चाहिए। उद्योग वर्ग से लेकर राजनैतिक शासक वर्ग इनके बिल्कुल विरूद्ध है।

जोइल रूट 2002

लोइल रूट ने सन् 2002 में लिखा कि और क्षमता अभिकरण (कारक) और गैर तकनीकी कटौतियों ने 17 प्रतिशत इसके वर्तमान करों में वृद्धि कर सकता है। विशेष तौर ऊर्जा स्तर पर ये योजनाऐं हमको बिना लोकप्रिय मापदण्डों से दूर रहने में हमारी मदद करेगी, उन्होंने अपने विचार में यह भी अभिव्यक्त किया है किये कार्य विद्युत परिषद इकाईयों द्वारा संचालित योजनाओं को शक्ति प्रदान करना नहीं है बल्कि राजनैतिक निर्देशों को कार्यान्वित करना उनकी कीमतों पर ध्यान केन्द्रित करना एवं बजट के वास्तविक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान करना एवं उचित रूप से निर्मित सूचना प्रणाली के क्षेत्र में इकाईयों को संचालित करना।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के वित्तीय विवरणों के विश्लेषणें की वर्तमान समय में प्रासंगिता

वित्तीय विवरणों के अध्ययन से पाया गया है कि वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 तथा 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 की वार्षिक रिर्पोटों के अध्ययन के उपरांत देखा गया है कि निगम की सम्पत्ति को क्षति पंहुचाई गई है, जिसमें बिजली के तारों की चोरी हो जाना। जिनकी राशि 96.98 करोड़ रूपये तथा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वसूली की राशि का लेखा अनुभाग में जमा न करना। राशि 797.14 करोड़ रूपये व टेण्डरों में ठेकेदारों द्वारा जमानत राशि को जमा न करना 2.5 करोड़ रूपये तथा समस्त स्त्रोतों पर कटौती की राशि का भुगतान ठेकेदारों द्वारा भुगतान न करना। राशि 95,00,000/–रूपये आदि।

1. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड चतुर्थ, कमला नगर, आगरा दुराचार, अनाचार अपराध में महावीर सिंह द्वारा 22–23 लाख रूपये की अनुमानित राशि का गबन किया गया। जिस पर एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
2. आगरा भण्डार में वित्तीय वर्ष 2012–13 में वैट के रूप में 3,31,301/–रूपये का ब्याज जुर्माना के रूप में भुगतान किया गया है।
3. विद्युत नगरीय वितरण खण्ड पंचम, शाहगंज आगरा में वर्ष 2005–06 में मनोज जौहरी कार्यालय सहायक, उपखण्ड आगरा, आवास–विकास तृतीय, आवास–विकास कॉलोनी में उपभोक्ताओं से रोकड़ संग्रह राशि 14,83,884/–रूपये की राशि बैंक में कम जमा की गई। बाद में 12,48,834/–रूपये 18 प्रतिशत ब्याज के साथ उनके वेतन से वसूले गये।
4. आगरा भण्डार में 31 मार्च 2012 में लम्बित 474 प्रविष्टियां जिनकी राशि 359.45 करोड़ रूपये हैं।
5. आगरा जनपद के फतेहाबाद, विद्युत वितरण खण्ड तृतीय 1,87,217/–रूपये आय को बिना किसी साक्ष्य के विलोपित कर दिया गया है। यह धनराशि आय के रूप में मान्य की जाती है तो परिक्षेत्र की हानियाँ 1,87,217/–रूपये कम हो जाती हैं।
6. विद्युत वितरण खण्ड मैनपुरी–
   दिनांक 29.10.2007 से 31.07.2009 में राजस्व पुस्तकें 143 मानिकचन्द्र को जारी की गयीं। जिनमें से 133 राजस्व पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। उपभोक्ताओं से रोकड़ प्राप्त संग्रह के लिए प्रयोग किया गया।
   रोकड़ प्राप्त 1,89,786.33
   जमा 1,80,189.19
   9,59,714/–रूपये कम जमा किये गये हैं।

उपखण्ड स्तर पर लेजर न तैयार करना तथा खण्ड स्तर पर वसूली का अनुमान न लगाना, यह राशि करोड़ों में होती है। इस राशि की वसूली के लिए निगम द्वारा अपने विभागों में सुधार करके इस राशि से उपभोक्ताओं के कल्याण तथा कर्मचारियों के हित कल्याण में खर्च कर राजस्व वसूली को और अधिक बढाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉवर कॉर्पोरेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में सौभाग्य योजना को लागू कर छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को संयोजन वितरित कर अपने राजस्व में विकास करने का एक सतत प्रयास किया है, जिसके कारण राजस्व वसूली में वृद्धि को देखा गया है। वर्तमान समय में विवरणों की समीक्षा कर प्रतिवेदन रिर्पोटों द्वारा हानि को कम किया जा सकता है। वित्तीय विश्लेषणों के द्वारा निगम में हानि को कम करने का प्रयास सार्थक सिद्ध किया जा सकता है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षकों की टिप्पणियों से भविष्य में सुधार के प्रयास किये जा सकते हैं। निगम के वित्तीय संस्थागत ढांचों में सुधार करने के कारणों की खोज करना वर्तमान समय की मांग है तथा नियम समय पर पी0डी0सी0 कर उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा किया जा सकता है तथा

विभाग कम यूनिटों को फुटकर यूनिटों में बेचकर तथा निगम द्वारा निगम में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाकर राजस्व वसूली को बढ़ाया जा सकता है तथा बकाया राशि को प्राप्त करने में सघन प्रयास की आवश्यकता होनी चाहिए। वित्तीय विवरणों में प्रावधानिक व्यय/अशोध्य ऋणों की राशि को कम किया जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

सुझाव

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के अर्न्तगत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा द्वारा विद्युत चोरी की जांच चैकिंग टीम द्वारा क्षेत्र में जांच के दौरान देखने में आया है कि जांच टीम के साथ उपभोक्ताओं द्वारा अभद्र व्यवहार तथा मारपीट की घटनांए होती हैं। ऐसी परस्थिति में टीम के सदस्यों में सुरक्षा का अभाव देखा गया है तथा क्षेत्र में विद्युत बकाया बिल की जांच करते समय तथा विद्युत भार चैकिंग करते समय उनके साथ उपभोक्ताओं द्वारा मारपीट करना तथा उन पर झूठे अनैतिक आरोप लगाये जाते हैं तथा उन पर अवैध वसूली करने के आरोप भी लगते हैं, उन्हें क्षेत्र में जाते समय पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अर्न्तगत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत वितरण का राजस्व वसूली करने के लिए किये गये उपायों के अर्न्तगत ऑनलाइन बिल पेमेंट को बढावा दिया जा रहा है। साथ ही डीवीवीएनएल द्वारा सरचार्ज में 50 प्रतिशत तथा मार्च में 100 प्रतिशत छूट देकर वसूली अभियान को और प्रभावी बनाया है। साथ ही सौभाग्य योजना के अर्न्तगत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन संयोजन देकर अप्रत्यक्ष रूप से दूरगामी विद्युत चोरी रोकना, लाइन हानियों को कम करने का प्रयास तेजी से किया है। साथ ही डीवीवीएनएल के राजस्व घाटे की भरपाई/पूर्ति के अर्न्तगत खर्चों में कटौती करना तथा आय में वृद्धि करने का लक्ष्य बनाया है एवं सचल दलों द्वारा छापामार कार्यवाही एवं सघन चैकिंग अभियान को युद्धस्तर पर चलाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *संदर्भ 1. वित्तीय विवरण मानक आईएएस 1, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की प्रस्तुति। पंहुच किए जाने वाले 24 जून 2007 2.3 डंसपाए तंि रिर्पोर्टिंग एमडीए अन्य प्रदर्शन वित्तीय वक्तव्यों के लिए नई कानूनी रूपरेखा (पीडीएफ) पुस्तकालय जानकारी देते। यूरोपीय संसद के पुस्तकालय। अभिगमन तिथि 06 जून 2013 4. मौलिक विश्लेषण नोट करने के लिए वित्तीय विवरण*
2. *(http://www.investopedia.com/university/fundamentalanalysis/notes.asp) }kjk Investopedia.com 5-foRrh; c;ku gks ldrk gks ewY; fVli.kh*
3. *(http://www.googobits.com/articles/1409-the-notes-to-the-financial-statements-may-be-worthnoting.htm) Googobits.com आगे पढ़ने 1. Alexander ब्रिट्टन द्वारा करने के लिए नोट्स , Jorissen, a. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग और विश्लेषण, दूसरा संस्करण 2005 ISBN 978.1.84480.201.2 बाहरी लिंक IFRS फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (http://www.ifrs.org)*
4. *वित्तीय लेखा मानक बोर्ड (http://www.fasb.org) (यू. एस.)*
4. *UN/CEAFCT*
5. *दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट से प्राप्त।*
6. *साहित्य प्रकाश एडवांस कॉमर्स एण्ड एकाउंटेंसी।*
7. *मैनेजमेंट एकाउंटिंग, लेखक एवं प्रकाशक डॉ0 एस0पी0 गुप्ता, साहित्य भवन, आगरा।*
8. *अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र।*
9. *Source: www.dvvnl.org*